RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 13 से 19 सितम्बर 2025 | भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष- 12 | अंक-58 | पृष्ठ- 8 | मूल्य- रु. 5 /-

Piyush Goyal Advocates Self-Reliance and Innovation in Steel Sector at ISA Steel Conclave

Minister Highlights FTA Negotiations and Job Creation Opportunities

New Delhi: Union Minister of Commerce and Industry, Shri Piyush Goyal, addressed the 6th ISA Steel Conclave on September 10, 2025, emphasizing India's capability to produce high-quality steel. He urged the industry to embrace self-reliance, assess import-export profiles for substitution opportunities, and collaborate with domestic supply chains to reduce foreign dependence, cautioning against predatory pricing by certain nations.

Trade and Policy Support

Goyal highlighted ongoing Free Trade Agreement (FTA) negotiations with multiple countries, including the EU and the recently concluded EFTA deal (effective October 1), to boost steel exports. He noted the inclusion of "melt and pour" conditions to protect Indian producers from low-cost imports, while the GST rate cuts are expected to enhance consumer demand, indirectly benefiting steel consumption.

Push for Domestic Manufacturing

The Minister stressed self-reliance in capital goods production, encouraging the steel sector to manufacture equipment domestically to create new business avenues and support India's industrial self-sufficiency. He also advocated for prefabricated steel structures in urban construction, citing cost savings and faster project completion, particularly in Mumbai's high-rise and slum rehabilitation projects.

Emerging Opportunities

Goyal identified shipbuilding as a transformative sector, leveraging India's 5-6 private shipyards and marine-grade steel capabilities to generate 10-12 million jobs. He is collaborating with the Ministry of Shipping for policy reforms to encourage local flagging, enhancing steel demand.

Industry's Role in Growth

Describing steel as the backbone of India's economy spanning infrastructure, defense, and medical devices Goyal set a target of exporting 50 million tonnes and producing 500 million tonnes domestically by 2047. He praised the sector's innovation and resilience, assuring government support in addressing raw material costs and ensuring iron ore access.

Conclusion

Goyal concluded that steel's evergreen nature, coupled with policy reforms and self-reliance, will drive India's journey to becoming a developed nation, urging the industry to set bold targets with government as a 24x7 partner.

फिच ने भारत का GDP ग्रोथ अनुमान बढ़ाया: अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव सीमित, घरेलू मांग और निवेश बने आधार

मजबूत आर्थिक गतिविधियों से भारत की वृद्धि में आत्मविश्वास

भोपाल: वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने 10 सितंबर 2025 को भारत के लिए वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। यह संशोधन भारत की मजबूत घरेलू मांग और निवेश गतिविधियों को दर्शाता है, जबकि अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को सीमित माना गया है।

फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि का मुख्य इंजन घरेलू खपत और निजी क्षेत्र का निवेश बना हुआ है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र में सुधार ने इस अनुमान को बल दिया। अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ, जो अगस्त 2025 से प्रभावी हैं, से निर्यात पर मामूली दबाव पड़ सकता है, लेकिन फिच का मानना है कि यह जीडीपी को केवल 0.2-0.3% तक प्रभावित करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू मांग की मजबूती इस झटके को संतुलित करेगी।

वैश्विक संदर्भ और चुनौतियाँ

अमेरिकी टैरिफ का असर मुख्य रूप से श्रम-गहन क्षेत्रों जैसे वस्त्र और रत्न-आभूषण पर पड़ा है, लेकिन भारत सरकार ने 40 देशों के साथ नए व्यापार समझौतों की योजना बनाई है। इसके अलावा, मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहने और मौद्रिक नीति के समर्थन से आर्थिक स्थिरता बनी हुई है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं जोखिम पैदा कर सकती हैं।

सरकारी प्रतिक्रिया और भविष्य

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस अनुमान को भारत की आर्थिक नीतियों की सफलता बताया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने का आह्वान किया। फिच का यह अनुमान भारत को उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी बनाता है, लेकिन दीर्घकालिक वृद्धि के लिए निवेश और नवाचार पर ध्यान देना जरूरी होगा।

निष्कर्ष

फिच का नया अनुमान भारत की आर्थिक प्रगति का प्रमाण है। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद, घरेलू शक्ति और नीतिगत समर्थन भारत को विकास के पथ पर अग्रसर रखेंगे।

एत्योहारी मांग और जीएसटी कटौती की उम्मीद से ऑटोमोबाइल रिटेल सेल्स में 2.8% की वृद्धि

बाजार में उत्साह के साथ ग्राहकों का बढ़ता रुझान

नई दिल्ली: भारत में ऑटोमोबाइल रिटेल सेल्स में अगस्त 2025 में 2.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो त्योहारी मांग और आगामी जीएसटी कटौती की उम्मीदों से प्रेरित है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अनुसार, दोपहिया और यात्री वाहनों की बिक्री में इस दौरान उछाल देखा गया। दोपहिया सेगमेंट में 3.5% और यात्री वाहनों में 2% की बढ़ोतरी हुई, जबकि तिपहिया वाहनों में मामूली गिरावट रही। प्रमुख कंपनियों जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी में भी गतिविधि तेज रही, जिनके शेयरों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है।

त्योहारी सीजन की शुरुआत, जिसमें नवरात्रि और दीवाली शामिल हैं, ने ग्राहकों को नई खरीद के लिए प्रेरित किया है। सरकार द्वारा जीएसटी में प्रस्तावित कमी—जैसे हाइब्रिड कारों पर 28%से 18% और छोटी कारों पर 18% से 5% से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ा है। टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाई, जबकि महिंद्रा के एसयूवी मॉडल्स और मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट कारों ने बाजारमें मजबूत प्रदर्शन किया। इन कंपनियों ने त्योहारी ऑफर और डिस्काउंट भी पेश किए, जो बिक्री को गति दे रहे हैं।

हालांकि, ग्रामीण बाजार में मांग अभी धीमी है, जहां मौसम और फसल की अनिश्चितता ने असर डाला है। शहरी क्षेत्रों में एसयूवी और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आई है। डीलरों का कहना है कि अगर जीएसटी कटौती जल्द लागू होती है, तो सेल्स ग्रोथ 5% तक पहुंच सकती है। वित्तीय संस्थाओं ने आसान EMI योजनाएं शुरू की हैं, जो ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं।

यह वृद्धि भारतीय ऑटो उद्योग के लिए सकारात्मक संकेत है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि त्योहारी सीजन में यह रुझान जारी रहेगा, बशर्ते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और कच्चे माल की कीमतें नियंत्रण में रहें। टाटा मोटर्स, महिंद्रा और सुजुकी की गतिविधियों पर नजर रखना निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

सुजुकी भारत में FY26 में फ्लेक्स-फ्यूल कारों की शुरुआत करेगा, डेयरी सहकारी समितियों के साथ बायोगैस साझेदारी बढ़ाएगा

हरित ऊर्जा और ग्रामीण विकास के लिए नई पहल

नई दिल्ली: सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने भारत को अपनी वैश्विक तकनीक रणनीति का केंद्र बनाते हुए FY26 (2025-26) में फ्लेक्स-फ्यूल वाहन (FFVs) लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। यह कदम भारत में कार्बन तटस्थता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी ने डेयरी सहकारी समितियों के साथ बायोगैस परियोजनाओं का विस्तार करने का भी निर्णय लिया है, जिसमें गाय के गोबर से सीएनजी उत्पादन शामिल है।

सुजुकी के प्रेजिडेंट टी सुजुकी ने बताया कि ये वाहन पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण पर चल सकते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। बायोगैस पहल के तहत, कंपनी स्थानीय डेयरी सहकारिताओं के साथ संयंत्र स्थापित कर रही है, जो 2025 से क्रमिक रूप से संचालन शुरू करेंगे। इससे ग्रामीण समुदायों की आय बढ़ेगी और भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। भारत ने FY25 में सुजुकी के वैश्विक राजस्व का 41% और लाभ का 45% योगदान दिया है, जो इस रणनीति को और महत्वपूर्ण बनाता है।

हल्के वजन वाली तकनीक और लीन-बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी काम चल रहा है, जो कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करेंगे। हालांकि, इस पहल की सफलता बुनियादी ढांचे और नीति समर्थन पर निर्भर करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल पर्यावरण को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।

Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor

Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor

Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

What You Need to Know About Cryptocurrency and Bitcoin!

Cryptocurrency has become one of the most discussed innovations of the 21st century. At its core, cryptocurrency is a digital or virtual form of money that uses cryptography for security. Unlike traditional currencies issued by governments, cryptocurrencies operate on decentralized networks, usually powered by blockchain technology. Among them, Bitcoin, launched in 2009 by the mysterious figure Satoshi Nakamoto, remains the most popular and influential.

Understanding Bitcoin and Its Function

Bitcoin was created as a peer-to-peer electronic cash system. Instead of relying on banks or intermediaries, transactions are recorded on a public ledger called the blockchain. Each "block" contains verified transactions, and once added, it cannot be altered. This makes Bitcoin secure, transparent, and resistant to fraud.

The limited supply of Bitcoin—capped at 21 million coins—adds to its value proposition, making it often referred to as "digital gold." Billionaire entrepreneur Elon Musk once remarked, "Bitcoin is a good thing," highlighting its potential as a store of value. Similarly, Microsoft co-founder Bill Gates acknowledged its transformative nature, saying, "Bitcoin is better than currency."

The Indian Perspective

In India, the journey of cryptocurrency has been both exciting and challenging. Millions of young investors have shown interest in digital assets, considering them an alternative investment avenue. Reports suggest that India has one of the largest user bases for cryptocurrency trading in the world.

However, regulatory uncertainty has often cast a shadow. In 2018, the Reserve Bank of India (RBI) restricted banking support to crypto platforms, causing a temporary setback. The Supreme Court later lifted the ban in 2020, reviving the industry. More recently, the government introduced taxation on digital assets, imposing a 30% tax on crypto profits and a 1% TDS on transactions, signalling recognition but also caution.

Despite hurdles, Indian startups like CoinDCX, WazirX, and ZebPay have emerged as significant players, making cryptocurrency accessible to the masses. Globally respected figures like Narendra Modi have also emphasized responsible usage. The Prime Minister, at a forum, stated: "It is important that democratic nations work together to ensure cryptocurrency doesnot end up in the wrong hands." This reflects India's cautious optimism—acknowledging the technology but warning against misuse.

Why Cryptocurrency Matters

Cryptocurrency is not just about trading for profit; it represents a broader shift in how money and finance work. From enabling cross-border payments without heavy fees to providing financial access for theunbanked, crypto holds revolutionary potential. In India, where a large population still remains outside formal banking, blockchain-based solutions could bridge gaps.

Additionally, many see Bitcoin as a hedge against inflation, particularly relevant in emerging economies. As billionaire investor Paul Tudor Jones said, "Bitcoin is a hedge against the great monetary inflation."

Final Thoughts

Cryptocurrency and Bitcoin are no longer fringe topics—they are shaping the future of money. For India, the challenge lies in balancing innovation with regulation. While risks like volatility, scams, and illegal usage cannot be ignored, the potential benefits for financial inclusion, investment, and digital progress are immense.

As Albert Einstein once noted, "In the middle of difficulty lies opportunity." For India and the world, cryptocurrency might just be that opportunity—if approached with wisdom and responsibility.

Dr. Irshad Ahmod Khan
Sub-Editor

अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत 40 देशों के बाजारों पर नजर, कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देगा: गिरिराज सिंह

वैश्विक व्यापार में आत्मनिर्भरता की नई रणनीति

नई दिल्ली: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को घोषणा की कि अमेरिका द्वारा भारतीय कपड़ा उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत 40 देशों के बाजारों में अपने निर्यात को बढ़ाने की योजना बना रहा है। यह कदम अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने और वैश्विक व्यापार में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में उठाया गया है। सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में कपड़ा निर्यात को दोगुना करना है, जो वर्तमान में 44 अरब डॉलर वार्षिक है।

मंत्री ने बताया कि सरकार अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जहां मांग बढ़ रही है। इसके लिए नई व्यापार नीतियों और सहायता पैकेजों की घोषणा की जाएगी, जिसमें छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि गुणवत्ता और नवाचार के साथ भारतीय कपड़ा उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना होगा।

इस पहल से रोजगार सृजन में भी वृद्धि होगी, क्योंकि कपड़ा क्षेत्र 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और निर्यात लागत कम करना इस रणनीति की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। सिंह ने उद्योग से उत्पादन बढ़ाने और टिकाऊ कपड़े पर ध्यान देने का आह्वान किया, जो अंतरराष्ट्रीय मांग के अनुरूप है। यह कदम भारत को अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों से उबरने और वैश्विक कपड़ा बाजार में मजबूत स्थिति बनाने में मदद कर सकता है।

Adani Power Teams Up with Druk Green for 570 MW Hydro Project in Bhutan

Strategic Alliance Boosts Regional Energy Security

New Delhi: Adani Power, India's leading private power producer, has partnered with Bhutan's state-owned Druk Green Power Corporation (DGPC) to develop a 570 MW hydroelectric project in Bhutan. The agreement, signed on September 6, 2025, in the presence of Bhutanese Prime Minister Dasho Tshering Tobgay and Adani Group Chairman Gautam Adani, marks a significant step in regional energy collaboration.
The Wangchhu hydroelectric project, a peaking run-of-river plant, will address Bhutan's winter power demand while exporting surplus electricity to India during the summer. Valued at approximately Rs 6,000 crore, the project will be executed under a Build, Own, Operate, Transfer (BOOT) model, with construction slated to begin in the firsthalf of 2026 andcompletion targeted within five years. The detailed project report is already finalized, signaling swift progress.
This initiative aligns with India's renewable energy goals and Bhutan's ambition to become a green energy hub. The partnership includes a Shareholders Agreement (SHA) and a Concession Agreement with the Royal Government of Bhutan, alongside an in-principal Power Purchase Agreement (PPA). Adani Power CEO SB Khyalia emphasized that the project will strengthen energy cooperation and create jobs, while DGPC Managing Director Dasho Chhewang Rinzin hailed it as a boost to Bhutan's sustainable development.
However, challenges such as environmental approvalsand cross-border infrastructure development remain .Analysts suggest this venture could pave the way for further Indo-Bhutan energy ties, potentially influencing regional power dynamics. As of 12:07 PM IST on September 10, 2025, the market is optimistic, with Adani Power's stock gaining traction.
This collaboration underscores a shared vision for clean energy, enhancing bilateral ties and supporting India's 500 GW renewable target by 2030.

Gold Demand Dips by 25% Sharply This Festive Season on Weak Buyer Sentiment

High Prices and Economic Uncertainty Dampen Traditional Purchases

Bhopal: Gold demand in India has declined by over 25% during the initial festive season, from Raksha Bandhan to Onam, as buyers scale back purchases due to soaring prices. The India Bullion & Jewellers Association (IBJA) reported a 28% drop in demand, totaling 50 tonnes compared to last year, marking the steepest decline in three years. This slump, noted as of September 10, 2025, is attributed to a 49% year-on-year price surge, with gold retailing at Rs 1,07,321 per 10 grams, inclusive of 3% GST.
High volatility and economic uncertainty have deterred consumers, with many opting for lighter, lower-karat jewellery (7-10 grams) instead of traditional heavy pieces. Surendra Mehta, IBJA's national secretary, highlighted that price instability is a key deterrent. However, investment demand for gold coins remains steady, while some jewellers report higher sales values despite reduced volumes.
The festive season, typically a peak period for gold purchases, has been impacted by inflation and shifting consumer preferences. Joy Alukkas of the eponymous jewellery firm noted a 15% volume drop till Onam. Analysts suggest that anticipated GST cuts and festive discounts might revive demand, but the industry is adapting by focusing on lightweight designs.
This trend reflects broader economic pressures, with buyers prioritizing essentials over luxury. The market awaits further data to assess if demand will rebound later in the season, as jewellers adjust strategies to meet evolving consumer needs.

Consumer Goods Firms Turn to Legal Experts for New GST Norms, Anti-Profiteering Compliance

Strategic Moves to Align with GST 2.0 Reforms

New Delhi: Major consumer goods companies in India are engaging top legal firms to navigate the complexities of the newly introduced GST 2.0 norms, effective September 22, 2025. With the government reducing tax rates on over 400 items and introducing anti-profiteering measures, firms like Hindustan Unilever, Nestlé India, and Dabur are seeking expert guidance to ensure compliance and avoid penalties.

The revised GST framework, featuring reduced rates on essentials like soaps (from 18% to 5%) and hybrid cars (from 28% to 18%), mandates companies to pass benefits to consumers. Legal experts from firms such as Khaitan & Co. and Cyril Amarchand Mangaldas areassisting in recalibrating pricing strategies and auditing supply chains to meet the National Anti-Profiteering Authority's (NAA) scrutiny. Non-compliance could attract fines up to 10% of the profiteered amount.

Industry leaders are also addressing the challenge of justifying price adjustments amid rising input costs. A senior executive from a leading FMCG firm noted that legal consultations are crucial to align with the new compliance regime while maintaining profitability. The move follows heightened regulatory oversight, with the government aiming to boost consumer spending during the festive season.

Analysts suggest this trend reflects a proactive approach to mitigate risks, especially as small and medium

enterprises (SMEs) face similar pressures. The legal support is expected to streamline operations, ensuring fair pricing and avoiding disputes. As the industry adapts, this collaboration could set a precedent for future tax reforms.

कोटक अल्टरनेट एसेट्स ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स के लिए 7,400 करोड़ रुपये की बोली लगाई, वेदांता की योजनाओं में अड़चन

ऊर्जा क्षेत्र में सत्ता संघर्ष की नई शुरुआत

नई दिल्ली: आज, 10 सितंबर 2025 को, कोटक अल्टरनेट एसेट्स (कोटक अल्ट्स) ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (जेपी पावर) के अनिवार्य परिवर्तनीय पसंदीदा शेयरों (CCPS) और कर्ज के लिए 7,400 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाई है, जिससे वेदांता की रणनीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह बोली जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के लिए वेदांता की हालिया विजयी बोली को प्रभावित कर सकती है, जो जेपी पावर में 24% हिस्सेदारी रखती है और वर्तमान में दिवालियापन प्रक्रिया से गुजर रही है।

कोटक अल्ट्स की पेशकश में 3,805 करोड़ रुपये CCPS और 3,600 करोड़ रुपये कर्ज शामिल हैं, जो जेपी पावर के नियंत्रण को एक तीसरे पक्ष के हाथों में ले जा सकता है। इससे वेदांता की जेएएल परप्रभावशाली स्थिति कमजोर हो सकती है, क्योंकि यह बोली जेएएल की मूल्यवान संपत्ति पर उसकी पकड़ को चुनौती देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ऊर्जा क्षेत्र में सत्ता संघर्ष को तेज करेगा।

वेदांता ने हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेज को हराकर जेएएल के लिए 17,000 करोड़ रुपये की बोली जीती थी, लेकिन कोटक की बोली ने बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है। सूत्रों के अनुसार, कोटक की हिस्सेदारी 25% तक पहुंच सकती है, जिससे ओपन ऑफर की स्थिति उत्पन्न होगी। यह स्थिति वेदांता के लिए रणनीतिक चुनौती है।

उद्योग विश्लेषकों का कहना है कि यह विकास जेपी पावर के कर्जदाताओं के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में बाजार की स्थिरता पर असर डाल सकता है। निवेशकों की नजर अब अगले कदमों पर टिकी है।

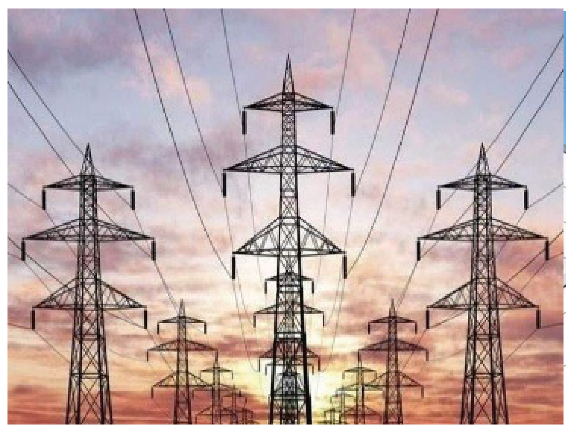

जीएसटी में कटौती से अधिक मरीजों को मिलेगी जरूरी दवाओं की पहुंच

स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत

नई दिल्ली: जीएसटी परिषद की हालिया बैठक में 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली कर दरों में कमी से कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी बीमारियों की जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को 18% से घटाकर 0% कर दिया गया है। यह कदम मरीजों के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि अब ये दवाएं सस्ती हो गई हैं। फार्मा इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे सालाना 5,000 करोड़ रुपये की बचत होगी, जो मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को लाभ पहुंचाएगी।

इस बदलाव से इंसुलिन, कीमोथेरेपी दवाएं और हृदय रोग की दवाओं की कीमतों में 15-20% की कमी आएगी। ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क (AIDAN) ने इसे स्वास्थ्य समानता की दिशा में बड़ा कदम बताया। हालांकि, दवा कंपनियों को इस लाभ को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सख्त निगरानी की जरूरत होगी, ताकि कालाबाजारी न हो। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम न केवल मरीजों की जेब पर बोझ कम करेगा, बल्कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर भी 18% जीएसटी हटने से बीमा कवरेज बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां दवाओं की पहुंच सीमित है, यह कदम क्रांतिकारी साबित हो सकता है। फिर भी, आपूर्ति श्रृंखला और जागरूकता अभियान पर ध्यान देना जरूरी होगा।

यह सुधार भारत को स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मरीजों को बेहतर जीवन की उम्मीद देता है।

डिश टीवी सेट-टॉप बॉक्स सब्सिडी को कम कर रहा, विविधीकरण की ओर बढ़ रहा

नई तकनीकों और बाजार विस्तार की रणनीति

भोपाल: डिश टीवी, भारत का प्रमुख डीटीएच प्रदाता, सेट-टॉप बॉक्स सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की शुरुआत कर रहा है। कंपनी का यह कदम अपने व्यवसाय को विविधीकृत करने और डिजिटल स्ट्रीमिंग जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार करने की रणनीति का हिस्सा है।

कंपनी के सीईओ मनोज डोभाल ने बताया कि सब्सिडी कम करने से लागत में कमी आएगी, जिससे डिश टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म और ब्रॉडबैंड सेवाओं में निवेश बढ़ा सकेगा। पिछले पांच वर्षों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं ने इस निर्णय को प्रभावित किया है। अब नए ग्राहकों को सेट-टॉप बॉक्स की कीमतें बाजार दरों पर देनी होंगी, हालांकि मौजूदा सब्सक्राइबर्स को कुछ समय तक राहत मिल सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम डिश टीवी को JioFiber और Airtel Xstream जैसे प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करने में मदद करेगा, जो पहले से ही डिजिटल सेवाओं में मजबूत हैं। कंपनी ने हाल ही में अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म 'Watcho' को बढ़ावा देने की योजना शुरू की है। हालांकि, ग्रामीण बाजारों में सब्सिडी हटने से ग्राहक आधार प्रभावित हो सकता है, जिसके लिए डिश टीवी को किफायती पैकेज पेश करने होंगे।

यह बदलाव भारत के डीटीएच उद्योग में एक नई दिशा की ओर इशारा करता है, जहां तकनीकी नवाचार और ग्राहक केंद्रित सेवाएं भविष्य की कुंजी होंगी।

Infosys Buyback 2025: A Golden Opportunity for Investors

Strategic Move Boosts Shareholder Value Amid Market Volatility

Bhopal: Infosys, India's second-largest IT firm, has announced its largest-ever share buyback of Rs 18,000 crore on September 11, 2025, offering a 19% premium at Rs 1,800 per share. This fifth buyback since 2017, executed via the tender offer route, signals strong management confidence and presents a lucrative opportunity for investors

The buyback, representing 2.41% of the company's equity, aims to enhance earnings per share (EPS) and return surplus cash to shareholders. With the stock down 20% year-to-date due to global IT spending slowdowns, this move could stabilize valuations. Investors can benefit from the premium and potential tax efficiency, especially retail shareholders, though tax implications post-April 2024 require consultation.

Analysts suggest this is an opportune time to invest, given Infosys' robust fundamentals Rs 24,500 crore cash reserves and a 21.1% operating margin inFY25. The stock's forward P/E of 21.6x, below its five-year average of 24.8x, indicates undervaluation. Positive market sentiment post-announcement saw a 5% intraday surge, with gains sustained into Friday trading.

However, risks like US tariff pressures and FII outflows warrant caution. Long-term investors may find value in holding, while short-term traders could capitalize on the tender offer. This buyback, amid festive demand, positions Infosys as an attractive bet for wealth creation.

Presolv360 Secures $4.7 Million from Elevation Capital and Partners

Funding Boost to Expand Online Dispute Resolution Services

Mumbai: Online dispute resolution (ODR) platform Presolv360 has raised $4.7 million in a funding round led by Elevation Capital, with participation from existing investor MGA Ventures and several angel investors. The aims to strengthen Presolv360's position in providing tech-enabled solutions for resolving disputes outside traditional courts.

Founded in 2017, Presolv360 collaborates with financial service organizations to offer mediation and arbitration services. The fresh capital will fuel its expansion beyond these offerings, enhancing legal-tech infrastructure and replicating systems for diverse dispute workflows. The company, which has processed thousands of cases in banking, securities, and employment disputes, plans to broaden its market reach.

The funding comes amid growing demand for efficient dispute resolution, with the platform reducing resolution times to 45-60 days compared to conventional methods. Industry experts view this as a strategic move to tap into India's burgeoning ODR market, projected to grow significantly. However, challenges like regulatory compliance and user adoption remain critical.

Presolv360's CEO highlighted the investment as a testament to the platform's potential to democratize justice. The company aims to leverage AI-driven tools to streamline processes further. With this financial backing, Presolv360 is poised to enhance its tech capabilities and scale operations, potentially setting a benchmark for ODR in India.

Aurva Secures $2.2 Million Led by Nexus Venture Partners for Data Security Growth

AI-Driven Access Monitoring to Boost Global Expansion

Bengaluru: Data security startup Aurva has raised $2.2 million in a seed funding round led by Nexus Venture Partners, announced on September 10, 2025. The round also saw participation from DeVC (backed by Z47) and angel investors, including former Meta executives Chris Bream, Rahul Sood, and Karandeep Anand, alongside Postman founders Ankit Sobti and Abhinav Asthana, and Cyware founders Akshat Jain and Anuj Goel.
Founded by Apurv Garg, Krishna Bagadia, and Akash Mandal, Aurva focuses on AI-driven access monitoring and observability, addressing real-time data usage in dynamic environments. The funds will support sales and marketing expansion, enhance security teams, and meet growing demand from enterprise clients in India, the US, and other global markets. Garg emphasized that existing tools fail to monitor sensitive data access effectively, a gap Aurva aims to fill.
This funding follows Aurva's emergence from stealth mode, with plans to leverage the capital to advance its AI observability capabilities. The startup's platform, designed for enterprises, aligns with rising cybersecurity needs amid increasing data breaches. Industry experts view this investment as a vote of confidence in India's tech startup ecosystem.
However, scaling globally will require navigating regulatory complexities and competition. With Nexus Venture

Partners' expertise, Aurva is well-positioned to strengthen its market presence. The raise underscores the growing importance of data security solutions, potentially positioning Aurva as a key player in the sector.

Fertiliser Sector Struggles with ITC Pile-Up Despite Recent Revision

Subsidy-Driven Price Inversion Challenges Industry Liquidity

New Delhi: The fertiliser industry in India continues to grapple with a significant accumulation of Input Tax Credit (ITC) despite recent revisions in raw material rates, as reported on September 10, 2025. Executives from major firms like R M Phosphates & Chemicals have highlighted that the subsidy-related price inversion—where output value falls below input costs—remains unresolved, locking up approximately ₹3,500 crore in working capital for large players alone.
The issue stems from the government's policy of selling fertilisers below cost to ensure affordability for farmers, with subsidies exempt from GST. This creates a disparity, as input costs attract GST while output values do not, leading to an ITC pile-up. Despite a reduction in raw material rates, the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) has urged Finance Minister Nirmala Sitharaman to clarify refund eligibility, warning of persistent liquidity pressures.
Industry leaders argue that allowing full ITC refunds could enhance cash flow, enabling investments in new projects. However, the government has yet to respond definitively, leaving companies in a financial bind. The situation is compounded by global supply chain disruptions and rising input costs, further straining the sector.
Analysts suggest that without policy intervention, the ITC issue could deter long-term growth, impacting India's agricultural productivity. The industry's plea for a streamlined refund mechanism aligns with the need to balance farmer support and corporate viability. As of 12:15 PM IST today, stakeholders await government action to mitigate this challenge, which could redefine the fertiliser sector's operational framework

Coal India Launches Tenders for 5 GW Renewable Energy Capacity

Strategic Shift to Diversify Amid Declining Coal Output

New Delhi: Coal India Limited (CIL), India's state-run mining giant, has issued tenders to develop 5 GW of renewable energy capacity, marking a significant pivot from its coal-centric operations. Announced today, September 10, 2025, at 12:05 PM IST, the initiative includes 3 GW of solar and 2 GW of wind power projects, aiming to bolster revenue streams amid a 3.5% production decline in the first five months of the fiscal year ending March 2026.
This move reflects CIL's strategy todiversify as coal demand softens due to tepid industrial activity. The company, which currently operates 0.2 GW of solar capacity, plans to expand its renewable portfolio to 9.5 GW by 2030. The tenders, open to domestic and internationalbidders, signal a commitment to sustainable growth and align with India's 500 GW renewable energy target by 2030.
Industry experts view this as a proactive step to mitigate risks from the coal sector's volatility. However, challengessuch as land acquisition and grid integration could delay progress. CIL aims to leverage its financial strength to fund these projects, with an estimated investment of Rs 25,000 crore over the next five years.
This transition could create thousands of green jobs and reduce India's carbon footprint. Stakeholders await further details on project timelines and partnerships, which could redefine CIL's role in the energy landscape.

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	25114	25638	25389	25251	25002	24864	24615	24477
BANK NIFTY	54809	55863	55356	55083	54576	54303	53796	53523
SENSEX	81905	83609	82800	82353	81544	81097	80288	79841
FINNIFTY	26363	27052	26713	26538	26199	26024	25685	25510
MIDCAP	13083	13519	13314	13199	12994	12879	12674	12559
ACC	1850	1890	1875	1862	1847	1834	1819	1806
AXISBANK	1106	1187	1148	1127	1088	1067	1028	1007
ABCAPITAL	291	314	304	298	288	282	272	266
BHARTIARTL	1904	1967	1946	1925	1904	1883	1862	1841
BHEL	229	251	240	235	224	219	208	203
BIOCON	365	380	376	370	366	360	356	350
CDSL	1547	1612	1590	1568	1546	1524	1502	1480
DATAPATTERN	2722	3062	2894	2808	2640	2554	2386	2300
ESCORTS	3685	3970	3895	3790	3715	3610	3535	3430
EICHERMOTOR	6874	7374	7153	7013	6792	6652	6431	6291
FEDERAL BANK	194	207	203	198	194	189	185	180
GRINFRAPOJECT	1278	1352	1330	1304	1282	1256	1234	1208
HDFCBANK	967	988	981	974	967	960	953	946
HCLTECH	1466	1574	1527	1496	1449	1418	1371	1340
HINDUNILVR	2582	2724	2691	2636	2603	2548	2515	2460
HAL	4744	5179	4964	4854	4639	4529	4314	4204
HYUNDAI	2558	2773	2697	2627	2551	2481	2405	2335
IOC	143	150	148	145	143	140	138	135
ICICIBANK	1417	1451	1436	1426	1411	1401	1386	1376
INFY	1525	1684	1614	1569	1499	1454	1384	1339
ITC	414	428	423	418	413	408	403	398
KOTAKBNK	1975	2055	2022	1998	1965	1941	1908	1884
LICHOUSING	567	591	580	574	563	557	546	540
LT	3579	3688	3642	3610	3564	3532	3486	3454
LUPIN	2040	2218	2136	2088	2006	1958	1876	1828
MARUTI	15307	16037	15708	15508	15179	14979	14650	14450
M&M	3591	3824	3773	3682	3631	3540	3489	3398
MGL	1299	1362	1335	1317	1290	1272	1245	1227
MAZGAONDOC	2930	3305	3122	3026	2843	2747	2564	2468
PFC	396	413	408	402	397	391	386	380
RECLTD	373	387	382	377	372	367	362	357
RELIANCE	1395	1431	1414	1404	1387	1377	1360	1350
SBIN	823	851	838	831	818	811	798	791
SUNPHARMA	1611	1672	1646	1629	1603	1586	1560	1543
SHRIRAMFINANCE	630	689	661	646	618	603	575	560
TITAN	3566	3764	3723	3645	3604	3526	3485	3407
TCS	3133	3314	3232	3182	3100	3050	2968	2918
TATAMOTORS	715	753	738	726	711	699	684	672
UPL	692	737	727	709	699	681	671	653
VALIENT	366	435	416	391	372	347	328	303
WIPRO	252	274	265	259	250	244	235	229

चीन की पाबंदियों के बाद भारत म्यांमार विद्रोहियों के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सौदा तलाश रहा

रणनीतिक संसाधनों के लिए नई साझेदारी

नई दिल्ली: भारत म्यांमार के विद्रोही समूह काचिन स्वतंत्रता सेना (KIA) के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (रेअर- अर्थ) के नमूने प्राप्त करने की योजना बना रहा है, क्योंकि चीन ने इन संसाधनों पर सख्त नियंत्रण बढ़ा दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, खनन मंत्रालय ने सरकारी और निजी कंपनियों से उत्तर-पूर्वी म्यांमार के KIA नियंत्रित खदानों से नमूने एकत्र करने को कहा है।

इस पहल में स्टेट-रन IREL और निजी कंपनी मिडवेस्ट एडवांस्ड मैटेरियल्स शामिल हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्नत उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का परीक्षण करेंगी। जुलाई में हुई एक ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय लिया गया। KIA ने नमूने एकत्र करना शुरू कर दिया है, और संभावित थोक निर्यात पर चर्चा चल रही है।

चीन, जो वैश्विक आपूर्ति का 70% नियंत्रित करता है, ने हाल ही में निर्यात पर पाबंदियां लगाईं, जिससे भारत ने वैकल्पिक स्रोतों की तलाश तेज कर दी है। यह कदम भारत की तकनीकी और रक्षा क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत करेगा। हालांकि, जटिल भू-राजनीति और लॉजिस्टिक चुनौतियां इस सौदे में बाधा बन सकती हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा, लेकिन स्थिरता के लिए दीर्घकालिक नीति की जरूरत होगी।

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in